5. Gujarat
6. Haryana
7. Himachal Pradesh
8. Jammu & Kashmir
9. Karnataka
10. Kerala
11. Madhya Pradesh
12. Maharashtra
13. Punjab
14. Tamil Nadu
15. Uttar Pradesh
16. West Bengal

UTS

1. Delhi
2. Daman & Diu

Escaping of Delinquent Children from Observation Home at Delhi Gate

4218. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is fact that fourteen delinquent children escaped from the Government run observation Home for boys at Delhi Gate, Delhi ;

(b) if so, the details thereof and reasons therefor ;

(c) whether the boys have since been traced ;

(d) whether Government propose to institute an inquiry about the functioning of this home ; and

(e) what action has been taken against the negligent officer of the Observation Home ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K V THANGKA BALU) : (a) Yes Sir. These children were destitute and neglected and not delinquent ;

(b) According to Govt. of N.C.T. of Delhi, the boys pierced the false ceiling by boning a hole in the night of 21-2-94 and escaped through the space between the C.G.T. sheet roofing and the false roofing to the big hole provided for exhaust. To facilitate the escape, the children removed the iron-bars fixed in between this hole. The children escaped due to negligence of Caretaker/Chowkidar of the Home.

(c) According to the Govt. of N.C.T. of Delhi, only four boys have been traced so far.

(d) As per the information made available by the Directorate of Social Welfare, Govt. of N.C.T. of Delhi, the Hon'ble Minister of Social Welfare, Govt. of Delhi, himself paid spot visit and made detailed inquiry alongwith the Director-cum-Secretary, Social Welfare on 22nd February, 1994. The detailed inquiry about the functioning of the Home has already been conducted. The inquiry also corroborated the negligence of two Caretakers/Chowkidars.

(e) The Govt. of N.C.T. of Delhi has found two Caretaking Staff members negligent in their watch and ward duty. They were immediately suspended.

नशा-मुक्ति केन्द्र

4219. श्री अजीत जोगी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा संचलित "नशा-मुक्ति केन्द्र" कोई शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो शुल्क के रूप में कितनी राशि ली जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि एकत्रित हुई;

(घ) क्या सरकार और अधिक नशा-मुक्ति केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० थंग्काबालू(क) से (ग) कल्याण मंत्रालय किसी निर्व्यसन केंद्र का सीधे ही संचालन नहीं करता है । किन्तु यह मंत्रालय लगभग 104 निर्व्यसन केंद्रों, 152 परामर्श केंद्रों तथा 15 उत्तरवर्ती देखभाल केंद्रों को सहायता-नुदान देता है । तथापि स्वास्थ्य मंत्रालय के ऐसे छः केंद्रीय अस्पताल है जिनमें निर्व्यसन यूनिटें उनके मनोचिकित्सा विभाग के अंग के रूप में कार्य करती है । वे प्रवेश के समय 10 रुपए प्रति व्यसनी की दर से नाममात्र का पंजीकरण शुल्क वसूल करते है ।

(घ) से (च) जी, हां । 1994-95 के दौरान इस मंत्रालय का 14 नये निर्व्यसन केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य है । यह मंत्रालय नशीली दवाओं के व्यसनियों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने हेतु निर्व्यसन केंद्रों की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को कुल अनुमोदित व्यय के 90% तक अनुदान उपलब्ध कराता है और शेष 10% स्वैच्छिक संगठनों को स्वयं वहन करना होता है । नये केंद्रों की अवस्थिति क्षेत्रीय जरूरत तथा उस क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के कार्य करने की इच्छा पर निर्भर करेगी ।